

समस्या मिल द्वारा सेवानिवृत्ति की श्रायु पर पहुंचने वाले श्रमिकों को मुआवजा देकर सेवानिवृत्त करके हल की जा रही है। छुट्टी की सुविधाओं को उदार बनाया जा रहा है और फालतू हुए श्रमिकों को दरी का सामान बनाने वाले श्रमिकों में, जहां कहीं संभव हो, लगाया जा रहा है। इन प्रयत्नों से ऐसे बहुत से श्रमिकों को रोजगार मिला है जो अन्यथा फालतू हो गये होते।

2. बंगाल पटसन श्रमिक संघ नाम की कोई यूनियन नहीं है। परन्तु पतकल मजदूर यूनियन कुछ मिलों में करवे बंद कर दिये जाने से उत्पन्न समस्या पर विचार करने के लिए इट औद्योगिक समिति की बैठक शीघ्र बुलाने के लिये निवेदन किया है और निम्न मुद्दा दिये हैं --

- (i) इट मिलों में पूर्वस्थिति बनाये रखना जैसी कि 20 अक्टूबर, 1968 को थी।
- (ii) काम के घंटों को घटाकर एक सप्ताह में 45 करना।
- (iii) कच्चा पटसन प्राप्त करने में राज्य-स्तरीय व्यापार शुरू करना। पटसन औद्योगिक समिति की एक बैठक 28 दिसम्बर, 1968 को बुलाई गई थी, लेकिन इसे स्थगित करना पड़ा, क्योंकि यह तारीख एक यूनियन को सुविधाजनक नहीं थी। इस समिति की बैठक यथाशीघ्र बुलाई जायेगी।

Manufacture of Ballot Boxes

*857. SHRI JYOTIRMOY BASU: Will the Minister of LAW be pleased to state:

(a) whether M/s. Khaitan Brothers of 4, Queen Park, Ballygunge, Calcutta had been given contracts to manufacture ballot boxes for the 1962 General Elections and, if so, whether there was any written agreement between the West Bengal Government and M/s. Khaitan Brothers;

(b) the number of ballot boxes supposed to have been manufactured by them as per agreement and the total quantity of steel supplied by Government for the purpose;

(c) the actual number of ballot boxes manufactured and the quantity of steel left unutilized with the manufacturers and whether this was returned to Government, and if not, the reasons therefor;

(d) whether it is a fact that the ballot boxes made by M/s. Khaitan Brothers had to be rejected because of an information received from one of the employees of the firm that the design of the box had been leaked out to a particular political party; and

(e) if not, whether Government would lay on the Table a statement explaining the whole position with regard to the manufacture of ballot boxes for the 1962 General Elections?

THE MINISTER OF LAW (SHRI GOVINDA MENON): (a) No, Sir.

(c) No manufacture of ballot boxes was undertaken for 1962 General Elections.

(b) to (d) Do not arise.

उत्तर प्रदेश में गोवध

858. श्री राम गोपाल शालबाबे; क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि राजस्थान और हरियाणा से बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में गाएँ लायी जा रही हैं और वहाँ उनका वध किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में गोवध पर प्रतिबन्ध है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को यह आदेश देने पर विचार कर रही है कि गोबंश के पशुओं के वध को रोकने सम्बन्धी कानून पर सख्ती से धमक किया जाये; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ). जी नहीं। अधिनियम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू किया जा रहा है। भारत सरकार के किसी आदेश की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

जिला रामपुर (उ० प्र०) में गोवंश के पशुओं का वध

859. श्री अंकार लाल बेरवा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के अपने दौरे के बाद सरकार को एक विस्तृत पत्र लिखा है जिसमें इस जिले में 50,000 गोवंश के पशुओं के वध के बारे में कहा गया है और उनसे अनुरोध किया गया है कि इसको रोके; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) जी हां

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से जानकारी इकट्ठी की जा रही है।

राजस्थान से भारी संख्या में पशुओं को अन्य स्थानों में ले जाना

860. श्रीयशपाल सिंह: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गम्भीर अकाल की स्थिति के कारण राजस्थान के जेसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर जिलों से पशुओं के भारी संख्या में अन्य स्थानों में जाने के तथ्य की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि राजस्थान में अकाल की स्थिति गम्भीर होने के कारण पशुओं का वध करने के लिये भारी संख्या में पशु उत्तर प्रदेश भेजे जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन पशुओं को अपने स्तर पर भेजने का है, ताकि इन पशुओं का वध रोका जा सके; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) राजस्थान सरकार इन जिलों से या उन राज्य के अन्य जिलों में या उन स्थानों में, जहाँ कि चारा और पानी उपलब्ध है, पशुओं के परिवहन की सुविधाएं, पहले ही प्रदान कर रही हैं, जिससे कि अगली मौसम तक पशुओं को संरक्षित रखा जा सके।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

Employees Provident Fund Organisation

*861. SHRI S. M. BANERJEE: Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Ministry of Law had earlier advised that the Employees Provident Fund Organisation was an industry; and

(b) if so, the reasons for changing their opinion now?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI HATHI). (a) Yes. In April, 1966.

(b) The present opinion is based on the recent judgments of the Supreme Court in the case of the Madras Gymkhana Club and the Cricket Club of India, Bombay.

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में औद्योगिक अशान्ति

*862. श्री भोलानाथ मास्टर : क्या धन तथा पुनर्वासि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :